धर्मानंद पंत

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

[जगन्नाथदास, जाफर इमाम, गोविंदा मेनन और जे. एल. कपूर, जे. जे.]

आपराधिक मुकदमा-आयोग पर अभियोजन पक्ष के गवाहों की परीक्षा

स्वामित्व-प्रक्रिया-दंड प्रक्रिया संहिता 503 और 506

आपराधिक कार्यवाहियों में एक सामान्य नियम के रूप में, जिन महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही पर अभियुक्त के खिलाफ मामला किया जाना है, उन्हें अदालत में दर्ज किया जाना चाहिए और आमतौर पर कमीशन जारी करना औपचारिक गवाहों या ऐसे गवाहों तक ही सीमित होना चाहिए जिन्हें अनुचित देरी या असुविधा के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य को उसकी उपस्थिति में और खुले न्यायालय में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को गवाहों से प्रभावी ढंग से जिरह करने का अवसर मिले और पीठासीन अधिकारी को गवाहों को सुनने और उनकी लापरवाही को नोट करने का लाभ और अवसर मिल सके जैसे गवाहों को सुनना और उनकी लापरवाही को नोट करना। देरी, खर्च या असुविधा के मामलों को छोड़कर गवाहों से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और विशेष रूप से पूछताछ के माध्यम से जांच का सहारा केवल अपरिहार्य मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, (1955 का 26) की धारा 97 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 503 के संशोधन से पहले, जिला

मजिस्ट्रेट या पीठासीन मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट कमिशन जारी नहीं कर सकता था, और यदि किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को गवाह से पूछताछ करना आवश्यक लगता है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना पड़ता था जो या तो आयोग जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

इसलिए एक ऐसे मामले में जहां महत्वपूर्ण गवाहों को पूछताछ के माध्यम से दोषी ठहराया गया था, और जांच के लिए मध्यस्थ को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, बल्कि परीक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया था, अदालत ने दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया और फिर से सुनवाई का आदेश दिया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार 1955 की आपराधिक अपील सं. 50

अलमोड़ा के न्यायिक अधिकारी द्वितीय और मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के 14 अप्रैल, 1952 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न 1952 की आपराधिक अपील संख्या 1115 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 7 जून, 1954 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील 1950 के आपराधिक मामले संख्या 271/19 में।

अपीलार्थी की ओर से एस. पी. सिन्हा और पी. के. चटर्जी।

प्रत्यर्थी की ओर से जी. सी. माथुर और सी. पी. लाल।

1957. 30 जनवरी।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश गोविंद मेनन द्वारा दिया गया था।

13 नवंबर, 1949 का पुलिस आरोप पत्र, जिसमें उस कार्यवाही की शुरुआत की गई थी, जिसमें यह अपील की गई थी, इस आशय का था कि अपीलार्थी, अल्मोड़ा में सिविल सर्जन के कार्यालय के प्रधान लिपिक ने प्रधान लिपिक के रूप में कार्य करने की अवधि के एक हिस्से के दौरान उन्हें सौंपी गई राशि का दुरुपयोग किया।हालांकि आरोप पत्र में विशेष रूप से दुरुपयोग की गई सही राशि का उल्लेख नहीं किया गया, इस मामले को तब ख़ारिज कर दिया गया जब भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किया गया, अर्थात्, 26 सितंबर, 1947 और 11 फरवरी, 1948 के बीच, उन्हें एक लोक सेवक के रूप में उनकी क्षमता में रु 1,118-10-9 ने उस राशि के संबंध में विश्वास का आपराधिक उल्लंघन किया। यह प्रश्न 2 के कॉलम 3 में विस्तृत राशियों से भी स्पष्ट है जो विद्वत विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई थी। निचली अदालत ने पाया कि अनुचित और असंतोषजनक स्थिति के कारण जिसमें खाते सिविल सर्जन के कार्यालय में रखे गए थे, जिसके लिए न केवल आरोपी बल्कि दो क्रमिक सिविल सर्जन जिम्मेदार थे, किसी भी अपराध को आरोपी के घर नहीं लाया गया और इसलिए उसे बरी कर दिया गया। राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसने 7 जून, 1954 के अपने फैसले द्वारा बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार कर दिया और अभियुक्त को धाराओं के तहत अपराध का दोषी पाया। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत उन्हें तीन महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। संविधान के अनुच्छेद 136 (1) (सी) के तहत विशेष अनुमति के लिए इस अदालत में एक आवेदन पर, इसे 30 जुलाई, 1954 के आदेश द्वारा प्रदान किया गया था, और यह इस तरह से दी गई विशेष अनुमति के अनुसरण में है कि अपील हमारे समक्ष है।

ऊपर उल्लिखित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश तक की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देना उपयोगी और आवश्यक होगा। कथित गबन का पता मार्च, 1948 में उस समय लगा जब मेसर्स मे एंड बेकर लिमिटेड ने सिविल सर्जन, अल्मोड़ा को इस आशय का एक अनुस्मारक भेजा कि उनके कुछ बिल अवैतनिक और बकाया थे। इसके बाद तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. कर ने मामले की जांच की और पाया कि अपीलार्थी, जो पदभार संभालने के समय प्रधान लिपिक थे, छुट्टी पर थे। अपीलार्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना भेजने पर, बाद वाले ने 5 मार्च, 1948 को प्रदर्शनी पी. 8 को एक पत्र भेजा, जिसमें कुछ बयान थे, जिन पर अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपीलार्थी आपराधिक गबन का दोषी था।

इसके बाद, अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित रूप से गबन किए गए धन को अपीलार्थी से बरामद किया गया और मार्च, 1948 में उन फर्मों को भुगतान किया गया जिनके बिल बकाया थे, लेकिन जिन्हें खातों में भुगतान किए जाने के रूप में दिखाया गया था। यह मामला केवल जून, 1949 में जांच के लिए पुलिस के हाथों में दिया गया था, जब अल्मोड़ा के उपायुक्त ने पुलिस उपाधीक्षक को मामले को देखने का आदेश दिया था। जाँच के बाद, 13 नवंबर, 1949 को एक आरोप-पत्र दायर किया गया और अंततः एस. पी. ओ द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया। अल्मोड़ा, 10 जुलाई, 1950 को, और कुछ समय बाद अदालत में प्राप्त किया गया था, जिसकी सही तारीख रिकॉर्ड से दिखाई नहीं देती है। 7 अगस्त, 1950 को एस. डी. एम. अल्मोड़ा की अदालत में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड

संहिता की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, गवाह को बुलाया गया लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी गवाह से कुछ समय के लिए पूछताछ नहीं की गई। 7 नवंबर, 1950 के आदेश-पत्र से पता चलता है कि जब फाइल प्रस्तुत की गई थी, तो एस. पी. ओ, अभियुक्त और अधिवक्ता अदालत में पेश हुए, लेकिन चूंकि महालेखाकार के कार्यालय से आवश्यक कागजात की मांग की जानी थी, इसलिए मामले को 14 नवंबर, 1950 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और एस. पी. ओ. को उस तारीख तक मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ऐसा लगता है कि 14 नवंबर, 1950 को कुछ नहीं किया गया था और मामले को 30 नवंबर, 1950 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और उस तारीख को मामले में लगे जिला सरकारी वकील; उन्होंने कहा कि महालेखाकार के कार्यालय में दस्तावेजों को बुलाना होगा और उनकी जांच करनी होगी। चूंकि मजिस्ट्रेट की राय थी कि यह एक अनिश्चितकालीन बात थी, इसलिए उन्होंने धारा के तहत फाइल पर हस्ताक्षर किए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249, अभिलेख कक्ष को इस निर्देश के साथ कि दस्तावेज़ उपलब्ध होने पर इसे बाहर निकाला जाएगा। हमारे सामने यह नहीं बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 249 को इस तरह के मामले में कैसे लागू किया जा सकता है, और न ही यह वारंट मामलों से निपटने वाले अध्याय के तहत आने वाले मामलों पर लागू होता है; लेकिन एक बात स्पष्ट है कि 30 नवंबर, 1950 के बाद, मामला काफी लंबे समय से हटा दिया गया है। जाहिर है कि अभियोजन पक्ष तैयार नहीं था और शायद गंभीर नहीं था। इसके बाद 4 जून, 1951 को जिला सरकार के वकील ने 15 जून, 1951 को कुछ गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए एस. डी. एम. को आवेदन किया और उसी का आदेश दिया गया। इसके बाद कार्यवाही न्यायिक अधिकारी, अल्मोड़ा को हस्तांतरित कर दी गई,

जिन्होंने 16 जून, 1951 को गवाहों से पूछताछ शुरू की।उन्होंने 16 जून, 1951 को पी. डब्ल्यू. 1 (शिब लाल तिवारी), 21 अगस्त, 1951 को पी. डब्ल्यू. 2 (बिशुन सिंह), उसी तारीख को पी. डब्ल्यू. 3 (मोहन सिंह), 25 अक्टूबर, 1951 को पी. डब्ल्यू. 4 (शिव लाल साह) और पी. डब्ल्यू. 5 (डी. एन. पांडे) और 10 नवंबर, 195 को हीरा लाल (पी. डब्ल्यू. 6) से पुछताछ की। इस बीच, 1 सितंबर, 1951 को जिला सरकार के वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों डॉ. डी. एम. कर, श्री आर. पी. कपूर और डी. एन. पांडे से पूछताछ करने के लिए अदालत में आवेदन किया और मजिस्ट्रेट ने उन्हें उसी तारीख को समन जारी करने का निर्देश दिया। अभिलेखों से यह देखा जाता है कि 7 सितंबर, 1951 को मजिस्ट्रेट को इलाहाबाद के सिविल सर्जन से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 507 (2) और साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत इस प्रभाव के लिए आवश्यक है कि चिकित्सा अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति वांछनीय है और उन गवाहों के लिए जांच के लिए एक आयोग जारी नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि एक आयोग की व्यवस्था की जा सकती है, तो इलाहाबाद में डी. एम. कर के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए इसकी व्यवस्था की जा सकती है। न तो यहाँ अपीलार्थी के वकील, और न ही उत्तर प्रदेश राज्य के श्री माथुर, हमें यह समझा पाए हैं कि सिविल सर्जन के पत्र में उल्लिखित धाराएँ किसी भी तरह से कैसे लागू होती हैं। हमें उत्तर प्रदेश के महालेखाकार का 14 सितंबर, 1951 का एक और पत्र मिलता है, जो 3 सितंबर के एक पत्र के जवाब में था। 1951, इस प्रभाव से कि महालेखाकार के कार्यालय के वरिष्ठ लेखा परीक्षक आर. पी. कपूर को 19 सितंबर, 1951 को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्हें महालेखाकार के कार्यालय के अप्रकाशित रिकॉर्ड से साक्ष्य देने के लिए अधिकृत नहीं

किया गया था, जिसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के तहत विशेषाधिकार का दावा किया गया था। 16 अक्टूबर, 1951 को, अपीलार्थी ने मजिस्ट्रेट को एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया था कि मामला मार्च, 1948 से चल रहा था और लंबे समय से चली आ रही कार्यवाही के कारण उसे बहुत परेशान किया गया था और अनुरोध किया गया था कि मामले का शीघ्र निर्णय लिया जाए। इन परिस्थितियों में, जिला सरकार के वकील ने 26 अक्टूबर, 1951 को एक आवेदन में कहा कि तीन गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, इसने यह भी कहा कि मामला लंबे समय से लंबित था। याचिका में आगे इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि अदालत में डॉ. डी. एम. कर और आर. पी. कपूर की उपस्थिति आवश्यक थी। उसी तारीख को मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया कि इन गवाहों से पूछताछ करने के लिए आयोग जारी किया जाए। 29 अक्टूबर, 1951 को अभियोजन पक्ष ने डॉ. बी. आर. जैन और श्रीमती मालती देवी जोशी की जाँच के लिए पूछताछ प्रस्तुत की। 14 नवंबर, 1951 को अभियोजन पक्ष ने श्री की जाँच के लिए पूछताछ प्रस्तुत की। जी. आर. के. टंडन, श्री लक्ष्मी शंकर, श्री विश्वाहथ और एम. एन. दुबे। डॉ. डी. एम. कर के संबंध में पूछताछ 10 नवंबर, 1951 को अदालत में दायर की गई थी। 12 नवंबर, 1951 को अभियुक्तों ने डॉ. डी. एम. कर के समक्ष रखे जाने वाले प्रश्न संख्या 5,6 और 9 पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन दिया, इस आधार पर कि वे ऐसे प्रमुख प्रश्न हैं जिन्हें मुख्य परीक्षा में नहीं रखा जा सकता है और आगे कहा कि डॉ. डी. एम. कर और श्री कपूर की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य दर्ज करने के लिए उपस्थिति आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए अदालत में उनकी प्रतिपरीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि यह संभव नहीं था, तो याचिका से जुड़ी प्रति-पूछताछ के साथ भेजी जा सकती है। उस आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने एक

आदेश दिया कि प्रश्नों को एक अलग भाषा में संशोधित किया जाना चाहिए जो उन्हें रखा गया है। इन गवाहों से पूछताछ बाद की तारीखों पर दायर की गई थी, जिसके विवरण का उल्लेख करना अनावश्यक है। हम अभिलेख से अभियोजन पक्ष द्वारा 14 नवंबर, 1951 के एक आदेश के साथ एक आवेदन पाते हैं, जिसमें कहा गया है कि जिन महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ के लिए आवेदन किया गया था, उनके अलावा चार और गवाहों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया कारण यह था कि अभियुक्त शीघ्र निर्णय के लिए चिंतित था और इसलिए गवाहों से पूछताछ करने का अनुरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दोहराया कि उसमें उल्लिखित चार गवाहों को तलब किया जा सकता है और उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जा सकती है। इस पर मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

- "सुनवाई की अंतिम तिथि पर यह तय किया गया था कि बाकी सभी पीडब्ल्यू की जांच कमीशन पर की जाएगी, और उस समझ पर श्री कपूर के लिए प्रश्न भी आज उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन अगर अभियोजन पक्ष चाहता है कि श्री कपूर का सबूत इतना आवश्यक हो, तो मैं उसे एक बार अदालत में बुलाने का केवल एक मौका देता हूं। उसे तार से सूचित किया जाना चाहिए कि वह 30-11-1951 पर मौजूद है, और यदि वह किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो उसके द्वारा तैयार की गई पूछताछ तुरंत भेजी जानी चाहिए। यह मामला लंबे समय से लटक रहा है। सुनवाई के अगले दिन केवल श्री आर. पी. कपूर को बुलाया जा सकता है। सभी गवाहों के लिए आयोग जारी किया जा सकता है क्योंकि वे अल्मोड़ा से बहुत दूर हैं।

इन कार्यवाहियों का परिणाम यह था कि, अन्य बातों के अलावा, दो सिविल सर्जनों जैसे महत्वपूर्ण गवाहों, जिनकी अवधि के दौरान कथित गबन हुई थी, के साथ-साथ लेखा परीक्षक से भी पूछताछ के माध्यम से पूछताछ की गई थी, भले ही अभियोजन पक्ष-जैसा कि आरोपी भी चिंतित थे कि कम से कम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण से अदालत में पूछताछ की जानी चाहिए। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रति-पूछताछ मुख्य परीक्षा में रखे गए प्रश्नों में उठाए गए बिंदुओं से संबंधित है। जिस अधिकारी को कमीशन जारी किया गया था, उसके सामने गवाहों द्वारा पूछताछ का जवाब दिया गया था और इस तरह से लिए गए सबूतों के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया है।

जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, अभियुक्त का बचाव यह था कि वितरित राशि को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया था और बाद के अवसरों पर वितरित किया गया था, हालांकि नकद पुस्तकों से पता चलता है कि वितरण पहले किया गया था। संक्षेप में, मामला यह आता है कि भले ही नकद बही में विशेष तिथियों पर संवितरण की प्रविष्टियां की गई हों, लेकिन वास्तविक संवितरण बाद में हुआ और बीच की अवधि के दौरान धन सुरक्षित में ही रह गया, जिसमें अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं था। यदि ऐसा है, तो आपराधिक गबन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने इस बचाव को अस्वीकार्य माना और पूर्व में निहित स्वीकारों को ध्यान में रखते हुए। पी. 8, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राशि का अस्थायी दुरुपयोग हुआ है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों और अभिलेख से देखे गए उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष के संस्करण या बचाव पक्ष के मामले में सच्चाई के बारे में या अन्यथा

कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक और वास्तव में अव्यवहारिक हो गया है। जिस स्तर पर अभियोजन पक्ष के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को आयोग पर पूछताछ द्वारा पूछताछ करने का निर्देश दिया गया था, यह स्पष्ट था कि अभियुक्त की याचिका अदालत के समक्ष नहीं हो सकती थी और इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि मामला बाद में कैसे आकार लेने वाला था।

सवाल यह है कि क्या इस तरह के अभियोजन में जहां एक सिविल सर्जन के कार्यालय के प्रधान लिपिक को एक विशेष अवधि के दौरान धन राशि के आपराधिक उल्लंघन के लिए आरोपित किया जा रहा है, और विशेष रूप से जहां गबन, यदि कोई हो, का पता बहुत पहले लगाया जा सकता था, अगर वरिष्ठ अधिकारियों ने रजिस्टरों की जांच करने और कार्यालय को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों के तहत उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने में जल्दबाजी की होती, तो यह कहा जा सकता है कि मुकदमा व्यवहार के स्थापित नियमों के सख्त अनुरूप है और उसी के उल्लंघन में नहीं है जहां महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अदालत के बाहर प्राप्त की गई है जिसे मामले से निपटना और निर्धारित करना है।

यह कानून की सभी प्रणालियों में प्राप्त आपराधिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित और मूल सिद्धांत है कि आपराधिक कार्यवाही में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य उसकी उपस्थिति में और खुली अदालत में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि आरोपी को बयान के ऐसे हिस्सों को चुनौती देने में सक्षम बनाया जा सके जिसे वह चुनौती देना चाहता है और पीठासीन अधिकारी को गवाह को व्यक्तिगत रूप से सुनने, उसके आचरण को

ध्यान में रखने और इस तरह के अवलोकन पर खुद के लिए पता लगाने का लाभ और अवसर मिल सकता है कि गवाह जो बयान देता है वह सच है या नहीं। जहाँ तक अभियुक्त का संबंध न्यायालय जैसे सार्वजनिक स्थान पर प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त की गवाही की सच्चाई या अन्यथा परीक्षण करने से भी है और जो एक गवाह द्वारा दिए गए उत्तरों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से विकसित हो सकता है। लेकिन जहां विशेष कारणों से अदालत में गवाह की उपस्थिति प्राप्त करना संभव नहीं है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता आयोग पर परीक्षा का प्रावधान करती है जो अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा सीधी परीक्षा और आरोपी या उसके वकील द्वारा प्रतिपरीक्षा हो सकती है। धारा 503, जैसा कि 1955 के संशोधन से पहले था, में प्रावधान किया गया था कि जहां संहिता के तहत किसी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी गवाह की परीक्षा न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, और ऐसे गवाह की उपस्थिति देरी, खर्च या असुविधा की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, तो ऐसा न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी उपस्थिति को समाप्त कर सकता है और उस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार गवाह की परीक्षा के लिए एक आयोग जारी कर सकता है। उप-धारा (2) में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता के तहत जांच परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ऐसे गवाह की परीक्षा के लिए आयोग जारी किया जाना चाहिए जिसका साक्ष्य न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है और ऐसे गवाह की उपस्थिति को देरी, खर्च या असुविधा की राशि के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, तो ऐसा मजिस्ट्रेट आवेदन के कारण

बताते हुए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट या तो आयोग जारी कर सकता है या आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। कमीशन पर गवाहों की परीक्षा के लिए प्रदान की गई विधियों में से एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 506 में निहित है, जो इस प्रकार हैः

(1) इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के पक्षकार, जिसमें एक आयोग जारी किया जाता है, क्रमशः किसी भी पूछताछ को लिखित रूप में अग्रेषित कर सकते हैं, जिसे आयोग को निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक समझ सकता है, और मजिस्ट्रेट अदालत, या अधिकारी जिसे आयोग का निर्देश दिया गया है, या जिसे इसे निष्पादित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, के लिए ऐसी पूछताछ पर गवाह से पूछताछ करना विधिसम्मत होगा;

(2) ऐसा कोई भी पक्ष ऐसे मजिस्ट्रेट, अदालत या अधिकारी के समक्ष अधिवक्ता द्वारा, या यदि हिरासत में नहीं है, तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है, और उक्त गवाह की जांच, प्रतिपरीक्षा और पुनः जांच (जैसा भी मामला हो) कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 97 द्वारा धारा 503 की उप-धारा (I) में 'जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट' शब्दों के स्थान पर 'कोई भी मजिस्ट्रेट' शब्द रखा गया था और उप-धारा (2) को हटा दिया गया था, लेकिन उप-धाराओं में एक परंतुक जोड़ा गया था, जिसका इस मामले की परिस्थितियों में उल्लेख करना अनावश्यक है। संशोधन का परिणाम यह है कि 1955 के अधिनियम XXVI की धारा 97 के अधिनियमन से पहले जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट आयोग जारी नहीं कर

सकता था और यदि ऐसे किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को आयोग पर गवाह की जांच करना समीचीन, आवश्यक या आवश्यक लगता है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना होगा जो या तो स्वयं आयोग जारी करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा। जिला मजिस्ट्रेट आयोग जारी करने या अनुरोध को अस्वीकार करने में न्यायिक रूप से कार्य कर रहा है और उसके आदेश अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन हैं।

इस धारणा पर कि आयोग नियमित रूप से जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश द्वारा स्थापित किया गया था, जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों द्वारा विचार किया गया था, सवाल यह है कि क्या अदालत में गवाहों से पूछताछ करने की सामान्य प्रथा से विचलित होने का पर्याप्त औचित्य था। हमें यह नहीं दिखाया गया है कि दो सिविल सर्जनों के साथ-साथ लेखा परीक्षक और अन्य गवाह की उपस्थिति बिना किसी देरी, खर्च या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती थी, जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित हो सकती है, और किसी ने यह सुझाव नहीं दिया है कि अल्मोड़ा के सिविल सर्जन का पद संभालने वाले दो अधिकारी उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य स्थान पर रहते थे, और ऐसी परिस्थितियों में भी घोर असुविधा या देरी और खर्च का सुझाव अनुचित नहीं है जो उन्हें अदालत से बाहर रखने को उचित ठहराए। यदि मजिस्ट्रेट ने इन गवाहों को समन जारी किया था और पाया था कि सामान्य मामलों में उनकी उपस्थिति प्राप्त करना मुश्किल था, तो वह अदालत में उपस्थिति को माफ करने की प्रक्रिया अपना सकता था। यह पता लगाने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए थे कि क्या सामान्य प्रथा का पालन नहीं किया गया होगा और ऐसी प्रक्रिया की असंभवता का पता चलने के बाद ही एक आयोग जारी किया जाना चाहिए था। केवल यह तथ्य कि कार्यवाही

असाधारण अवधि के लिए उन कारणों से लंबी हो गई है जो रिकॉर्ड में बहुत अधिक नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इस धारणा के लिए जगह देते हुए कि संबंधित उच्च अधिकारी राशि को ध्यान में रखते हुए मामले को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे, आयोग जारी करने के लिए अपने आप में कोई आधार नहीं हो सकता है; यानी, केवल मामले के निपटारे में देरी, और अदालत में गवाह की गवाही प्राप्त करने में देरी नहीं। आयोग के मुद्दे के लिए रिकॉर्ड पर कोई संभावित औचित्य नहीं दिखाई देता है और इससे भी अधिक केवल पूछताछ के मुद्दे के लिए।

सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आयोग जारी करना धारा 75-78 द्वारा नियंत्रित होता है। और जिसमें से 026, r. 1 उन मामलों को निर्धारित करता है जिनमें एक अदालत एक गवाह से पूछताछ करने के लिए एक आयोग जारी कर सकती है। आम तौर पर जब कोई व्यक्ति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता है और उसे संहिता के तहत अदालत में उपस्थित होने से छूट नहीं है या जो बीमारी या दुर्बलता के कारण अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो उससे अदालत में पूछताछ की जानी चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 75-78 के तहत और 0 26, आर. 4, एक गवाह से आयोग पर पूछताछ की जा सकती है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी है, या एक व्यक्ति जो अदालत में पूछताछ की जाने वाली तारीख से पहले ऐसी सीमाएं छोड़ने वाला है, या सरकार की सेवा में कोई भी व्यक्ति जो अदालत की राय में अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचाए बिना उपस्थित नहीं हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों से पूछताछ के लिए ऐसी कोई सीमाएं नहीं लगाई गई हैं। लेकिन यह अपने आप में पीठासीन अधिकारी को एक गवाह की जांच करने के लिए एक आयोग जारी करने में अधिक सावधानी और सावधानी बरतनी

चाहिए, क्योंकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति का अंतर्निहित अधिकार है कि वह अपने खिलाफ खुली अदालत में और उसकी उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज करे और जहां उस तरीके से कोई विचलन आवश्यक है, वह असाधारण मामलों तक सीमित होना चाहिए और दंड प्रक्रिया संहिता प्रदान करती है कि इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग कैसे और कहां किया जाना चाहिए।

क्वीन-एम्प्रेस बनाम टी. बर्क (') मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष के लिए सभी महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य को इस आधार पर स्वीकार करने की अनुमति देना उचित नहीं है कि गवाह के लिए अदालत में उपस्थित होना असुविधाजनक होगा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के 503 और 506 का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और केवल सबसे स्पष्ट संभावित मामलों में, मोहम्मद शफी बनाम सम्राट (2) में निर्धारित किया गया है। इस मुद्दे पर केस लॉ को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्णय लिया जाना है। एक सामान्य नियम के रूप में यह कहा जा सकता है कि जिन महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही पर अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला स्थापित किया जाना है, उनकी अदालत में जांच की जानी चाहिए और आमतौर पर कमीशन जारी करना औपचारिक गवाहों या ऐसे गवाहों तक ही सीमित होना चाहिए जिन्हें मामले की परिस्थितियों में अनुचित देरी या असुविधा के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। कमीशन पर गवाहों से पूछताछ करने का विचार मुख्य रूप से मुख्य रूप से इच्छुक पक्षों के अलावा अन्य गवाहों के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए है जैसे कि शिकायतकर्ता या कोई भी व्यक्ति जिसकी गवाही अभियोजन मामले को साबित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। संक्षेप में, एक आपराधिक मामले में गवाहों से देरी, खर्च या असुविधा के चरम मामलों को छोड़कर

पूछताछ नहीं की जानी चाहिए और विशेष रूप से अपरिहार्य स्थितियों में पूछताछ के माध्यम से प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला विवेकाधिकार न्यायिक है और इसका प्रयोग हल्के या मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में, हमें यह ध्यान रखना होगा कि दो सिविल सर्जनों और लेखा परीक्षक का साक्ष्य अपीलार्थी के खिलाफ मामले का आधार होगा और मामला होने के कारण, हमें ऐसा लगता है कि अदालत में उनकी जांच की जानी चाहिए थी। जैसा कि हमारा विचार है कि मजिस्ट्रेट ने आयोग पर आवश्यक गवाहों से पूछताछ करने में अनुचित तरीके से काम किया है, हम महसूस करते हैं कि आरोपी पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है।

ऊपर उल्लिखित कार्यवाहियों की समीक्षा से यह भी प्रतीत नहीं होता है कि मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 503 (2) में अनुध्यात आवेदन के साथ जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था। जिला स्थायी वकील के अनुरोध के जवाब में मजिस्ट्रेट ने स्वयं निर्देश दिया कि आयोग को 26 अक्टूबर, 1951 को जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा 12 नवंबर, 1951 के आदेश द्वारा कथित प्रमुख प्रश्नों को संशोधित करने और एक शैली और बोलचाल में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था जो प्रश्नों की प्रमुख प्रकृति के दोष को ठीक करेगा। 14 नवंबर, 1951 के आदेश से यह भी नहीं पता चलता है कि जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का कोई प्रयास किया गया था, क्योंकि हम आदेश-पत्र में मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों को पाते हैं, जिसका उल्लेख पहले के चरण में किया गया था।

हमने स्वयं निचली अदालतों से मांगे गए मूल अभिलेखों की जांच की है और हमारी जांच का परिणाम इस पर आता है। मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 1951 को दिए गए आदेश की निरंतरता में, कि इच्छा के अनुसार आयोग जारी किए जाएंगे, 19 नवंबर, 1951 को उन्होंने स्वयं 503 और 506, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों की जांच करने के लिए एक आयोग जारी किया है । न्यायिक अधिकारी द्वितीय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा ने जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को संबोधित करते हुए कहा है कि मुकदमे के उद्देश्य के लिए अभियोजन पक्ष और जिले की ओर से गवाह के रूप में मार्जिन में नामित व्यक्ति से पूछताछ करना आवश्यक था। मजिस्ट्रेट, लखनऊ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 503 और 506 के प्रावधानों के तहत अधिकार के साथ पुछताछ आदि पर उक्त गवाह की जांच और प्रतिपरीक्षा करने के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाता है। आयोग को निष्पादन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को भेजने के पक्ष में, जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा को समन प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह उसी तारीख को कमीशन पर अन्य गवाहों से पूछताछ करने के लिए समन भी जारी किए गए हैं और उन सभी को आयोग का पालन करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को भेज दिया गया है। यह कहीं भी नहीं देखा गया है कि अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने स्वतंत्र निर्णय या न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग किया है जैसा कि उप-धारा (2) से धारा 503, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतिम खंड में विचार किया गया है कि क्या ऐसा कोई आयोग जारी किया जाना चाहिए या नहीं। संहिता में इस बात पर विचार किया गया है कि जिस जिला मजिस्ट्रेट को मुकदमा चलाने वाला मजिस्ट्रेट आयोग जारी करने का अनुरोध करता है, उसे स्वयं आयोग जारी करना चाहिए या आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि आवेदन करने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन का कारण

बताना चाहिए। हमें अभिलेख से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे पता चले कि अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट, जिन्हें संहिता के तहत आयोग जारी करने का अधिकार होना चाहिए, ने संहिता के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया है। रिकॉर्ड से केवल इतना ही पता चल सकता है कि अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आयोग को भेजने के लिए एक अग्रेषण प्राधिकरण के रूप में काम किया है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अल्मोड़ा के जिला मजिस्ट्रेट के पास या तो मुकदमा चलाने वाले मजिस्ट्रेट के अनुरोध को स्वीकार करने और आयोग जारी करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति थी, और किसी भी तरह से दिया गया आदेश मामले पर पूरी तरह से विचार करने के बाद न्यायिक होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इस तरह का मामला होने के कारण, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि पूछताछ पर गवाहों की परीक्षा को उचित ठहराने के लिए आवश्यक अभ्यास के एक प्राथमिक नियम का पालन नहीं किया गया है। यह बात इस कारण से महत्वपूर्ण है कि यदि आयोग जारी करने की वैधता के लिए आवश्यक पूर्व-आवश्यकता का पालन नहीं किया गया है, तो इस प्रकार लिया गया साक्ष्य अनुचित होगा और अभियुक्त के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह एक दोष है जो मामले की जड़ तक जाता है और सामग्री में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है और गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड से पूरी तरह से अलग करना होगा।

इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, कानून के अनुसार, मामले को फिर से सुनवाई के लिए पहली बार अदालत में भेजते हैं। अदालत में जिन गवाहों से पहले ही

पूछताछ की जा चुकी है, उनसे फिर से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि अदालत इसे आवश्यक नहीं समझती।

अपील की अनुमति दी गई। मामला फिर से सुनवाई के लिए प्रतिपेषण पर लिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सपना राजपुरोहित की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।